वा. की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता की आवश्यकता का आकलन किया है। दूसरे ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जाएगा और नौवीं योजना प्रस्तावों के समेकन के साथ उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा।

कच्छ और बनासकांठा का औद्योगिक विकास

2609. **श्री चिमनभाई हरीभाई शुक्ला :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजनावधि के प्रारम्भ में गुजरात के कच्छ और बनासकांठा जिलों में कुल कितने व्यक्ति बेरोजगार थे ;

(ख) इन जिलों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन-कौन से क्षेत्र उपलब्ध थे ;

(ग) इनमें सरकारी और निजी क्षेत्र का अनुपात कितना-कितना है ;

(घ) क्या ये जिले आठवीं योजनावधि के प्रारम्भ में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास दर से बहुत पीछे चल रहे थे ; और

(ङ) सरकार द्वारा कच्छ और बनासकांठा जिलों को राष्ट्रीय औद्योगिक मुख्य धारा में शामिल करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सवनूर) : (क) से (घ) रोजगार एवं बेरोजगारी तथा औद्योगिक वृद्धि के बारे में जिलेवार सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का विकास करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। राष्ट्र की औद्योगिक मुख्य धारा में पिछड़े इलाकों को विकसित करके लाने की दृष्टि से केन्द्र सरकार ने इन क्षेत्रों के त्वरित औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए 1988 में विकास केन्द्र स्कीम की घोषणा की थी। गुजरात के लिए तीन विकास केन्द्रों अर्थात कच्छ जिले में गांधी धाम, बनासकांठा जिले में पालमपुर और भड़ोच जिल में वागरा का अनुमोदन किया गया इसके लिए 31 मार्च, 1997 तक केन्द्र सरकार द्वारा क्रमशः 100 लाख रुपये, 100 लाख रुपये और 1000 लाख रुपये की धन राशि जारी कर दी गई है।

गुजरात सहित देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में केन्द्र सरकार अनेक विशेष रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बड़े गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम रोजगार प्रदान करते हैं, वह हैं—एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना एवं रोजगार आश्वासन स्कीम। शहरी क्षेत्रों में दो गरीबी उन्मूलन स्कीमें चल रही हैं अर्थात नेहरू रोजगार योजना और प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। यह कार्यक्रम भी रोजगार प्रदान करते हैं। प्रधान मंत्री की रोजगार योजना का कार्यान्वयन केन्द्रीय योजना स्कीम के रूप में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किया जा रहा है।

Release of funds for development works in the North-East

2610. SHRI KARNENDU BHATTACHARJEE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware that a sum of Rs. 6100 crore was announced by the Prime Minister for development works in North-East;

(b) if so, how much funds have so far been released and what is the progress in this regard; and

(c) if not what do Government propose to do in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRIMATI RATNAMALA DEHARESHWAR SAVANOOR): The then Prime Minister issued

statement on 27th October, 1996 at Guwahati pertaining to new initiatives for NE region comprising programmes/schemes/projects for economic development of seven North-Eastern States. The estimated cost of the projects/schemes envisaged in the statement amounted to about Rs. 6100.00 crore.

(b) and (c) The details of progress of implementation of these programmes/schemes/projects, funds released and balance action required is given in the Annexure. (*See* Appendix 181, Annexure No. 71.)

Confining the role of Planning Commission

2611. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to confine the role of Planning Commission to a few sectors of activities that require detailed planning and delegate the responsibility of power for planning in regard to the remaining sectors to Central Ministries and States;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRIMATI RATNAMALA DEHARESHWAR SAVANOOR): (a) to (c) The role of Planning Commission continue to remain same as given in the Resolution of the Cabinet Secretariat dated the 15th March, 1950 setting up the Planning Commission. However, the Approach Paper to the Ninth Plan envisage formulation and implementation of the Ninth Plan in the spirit of Cooperative Federalism which inter alia include greater role for the States in the formulation as well as implementation of the Plan Schemes. The Approach Paper also envisage preparation of detailed sectoral plans for certain sectors like power, selected medium and major irrigation projects, critical communication and agricultural development and infrastructure etc.

विश्व बैंक निधि का झारखण्ड क्षेत्र में दुरुपयोग

2612. श्री ज्ञान रंजन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झारखण्ड क्षेत्र में विश्व बैंक द्वारा चलायी जा रही योजनाओं में विश्व बैंक द्वारा प्रदान की गयी निधियों का दुरुपयोग हो रहा है और यह कभी भी एक बड़े घोटाले के रूप में आ सकत है ;

(ख) क्या कुछ उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े-बड़े ठेकेदारों को ही काम मिलता है ;

(ग) क्या ये ठेकेदार 20 प्रतिशत शुद्ध मुनाफे पर छोटे-छोटे ठेकेदारों को काम दे देते है ;

(घ) क्या काम करवाने के लिए नियमित निविदा मंगवायी जाती है, और जिनकी सबसे न्यूनतम दर होती है उन्हीं को काम दिया जाता है ; और

(ङ) क्या सरकार इन परिस्थितियों को देखते हुए इसकी जांच कराएगी और जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सवनूर) : (क) से (ङ) झारखण्ड प्राप्त स्कीमों का प्रतिपादन एवं कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है तथा इनकी मानीटरिंग राज्य संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा की जाती है। इन स्कीमों के कार्यान्वयन में योजना आयोग की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है ।